(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन मामलों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन निदेशों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). केरल के अलावा अन्य राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि पिछले चार महीनों में ऐसा उदाहरण नहीं है जहां केन्द्रीय सरकार के किन्हीं निदेशों का पालन न किया गया हो। जहां तक केरल का सम्बन्ध है 18 सितम्बर, 1968 को राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र में कर्मचारियों को हड़ताल के लिये उकसाने और/अथवा हिंसा के लिये उत्तेजित करने तथा उन कर्मचारियों को, जो 19 सितम्बर, 1968 को काम पर जाना चाहते थे, डराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने तथा गिरफ्तारी समेत उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिये जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। उस पर 19 सितम्बर को केरल सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया गया जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों पर एक दायित्व डाला गया है कि उनकी कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायगा जिससे संसद् द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। आगे यह भी बतलाया गया कि कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने या उत्तेजित करने से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के उपबन्ध ऐसे एक नियम के भाग हैं। इस पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तथा उपयुक्त कार्यवाहियां की जा रही हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का सुझाव देने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया था।

मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*728 **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के उन वर्तमान तथा भूत-पूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में जांच की गई है अथवा की जा रही है ;

(ख) उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन मंत्रियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*729. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर केन्द्रीय सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं के कितने कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1968 को हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया ;

(ख) उनके मंत्रालय तथा विभाग में उक्त हड़ताल में भाग लेने वाले कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा कितने

कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया : और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा कितने व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई शिक्षा संस्था नहीं है ।

(ख) (i) मुअत्तल कर्मचारियों की संख्या 6

(ii) सेवा से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या.. .. कोई नहीं ।

(ग) (i) गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों की संख्या.... 6

(ii) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया . कोई नहीं

Publication of India's Maps

*730. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the Surveyor General of India possesses exclusive right for publication of India's maps;

(b) if so, what are the conditions under which maps of India are allowed to be printed and published by other agencies in India and abroad.,

(c) whether the Surveyor General has the exclusive Copyright to print and publish the maps of other countries., and

(d) if so, the names of such countries, and the terms and conditions under which these rights have been acquired?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b). No, Sir. The Survey of India, however, is the main Government agency for all geodetic and topographical surveys in India for the preparation of maps of India. Private publishers can also publish maps of India, but they have been advised to have the external boundaries of India as depicted on their maps vetted by the Survey of India, before publishing them.

The copyright of the Survey of India maps vests in the Government of India and the Surveyor General may permit reproduction of these maps or any other cartographic information on payment of royalty charges.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें

*731. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की एक योजना को, आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रारंभ में एक प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जाए । दिल्ली विश्वविद्यालय में योजना को कार्यान्वित करने के लिए इसके कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरों को दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।